भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2858
दिनांक 18.03.2025 को उत्तरार्थ

इंटरनेट और ई-पंचायत

2858 .श्री ओमप्रकाश भूपाल सिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकरः
श्री संजय उत्तमराव देशमुखः

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों की सभी ग्राम पंचायतों को इंटरनेट/ई-पंचायत सुविधा प्रदान की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सभी राज्यों को इंटरनेट सुविधाएं कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है;

(ख) देश मे इंटरनेट से जुड़े गांवों का राज्यवार और जिलावार ब्यौरा विशेषकर महाराष्ट्र के उस्मानाबाद और वाशिम-यवतमाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में क्या है;

(ग) देश के उन गांवों में इंटरनेट सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम क्या हैं, जहां अभी तक इंटरनेट सुविधा प्रदान नहीं की गई है;

(घ) देश में उन पंचायतों का ब्यौरा क्या है और पंचायतों की संख्या कितनी है जहां इंटरनेट/ई-पंचायत सुविधा प्रदान की गई तथा पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का महाराष्ट्र राज्य सहित राज्यवार, जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ङ) आज की तिथि तक उन गांवों में इंटरनेट सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है, जहां इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नहीं है; और

(च) उक्त संबंध में सरकार द्वारा, विशेषकर अस्मानाबाद और वाशिम-यवतमाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में, कार्यान्वित की जा रही अन्य योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री
(प्रो. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) और (ख) : पंचायती राज मंत्रालय डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत, देश के सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) को लागू कर रहा है। इसका उद्देश्य पंचायतों के कामकाज में सुधार लाना और उन्हें अधिक पारदर्शी, जवाबदेह तथा प्रभावी बनाना है। मंत्रालय ने पंचायत की आयोजना, लेखांकन और बजटन जैसे कार्यों को सरल बनाने हेतु एक लेखा एप्लिकेशन ई-ग्राम स्वराज को लॉन्च किया है। मंत्रालय ने विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं को वास्तविक समय पर भुगतान करने हेतु ग्राम पंचायतों (जीपी) के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ ई-ग्राम स्वराज भी एकीकृत किया है। अब तक, वर्ष 2024-25 के लिए 2,54,508 ग्राम पंचायत विकास योजनाएं (जीपीडीपी) तैयार की गई हैं जो

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध हैं। वर्ष 2024-25 के लिए ई-ग्राम स्वराज के तहत राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गई प्रगति **अनुलग्नक-I** में दी गई है। इसके अलावा, महाराष्ट्र द्वारा, विशेष रूप से उस्मानाबाद और वाशिम-यवतमाल संसदीय क्षेत्र में तैयार की गई ग्राम पंचायत विकास योजनाएं (जीपीडीपी) नीचे दी गई हैः-

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/ जिला पंचायत	**कुल ग्राम पंचायत**	जीपीडीपी **2024-25**
महाराष्ट्र	27951	27744
लातूर	786	784
उस्मानाबाद	622	618
सोलापुर	1024	1011
वाशिम	491	491
यवतमाल	1201	1200

इसके अतिरिक्त, सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) द्वारा वित्त पोषित भारतनेट परियोजना को चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है। यह आधारभूत सुविधाओं जैसे ग्रामीण क्षेत्रों ,ग्राम पंचायतों ,डाकघरों, स्कूलों, अन्य सरकारी संस्थानों और निजी क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी के प्रावधान के लिए टीएसपी/आईएसपी को लीज पर दिया गया है।

मार्च 2025 तक, नियोजित 2,69,020 ग्राम पंचायतों में से, 2,18,347 ग्राम पंचायतों को भारतनेट परियोजना के तहत हाई स्पीड इंटरनेट सेवाएँ प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। ब्रॉडबैंड सेवाएँ प्रदान करने के लिए तैयार की गई ग्राम पंचायतों का राज्यवार विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है। इसके अलावा, महाराष्ट्र में, विशेष रूप से उस्मानाबाद और वाशिम-यवतमाल संसदीय क्षेत्र में, तैयार की गई ग्राम पंचायतों का विवरण नीचे दिया गया हैः-

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/ जिला पंचायत	**कुल ग्राम पंचायतें**	**तैयार सेवा बिन्दु** *
महाराष्ट्र	27951	24778
लातूर	786	792
उस्मानाबाद	622	629
सोलापुर	1024	817
वाशिम	491	488
यवतमाल	1201	1127

** डेटा भारतनेट यूएनएमएस डैशबोर्ड से प्राप्त किया जाता है, और कुछ ग्राम पंचायतों में कई सेवा-तैयार बिंदु हो सकते हैं।*

इसके अलावा, दिनांक 04.08.2023 को कैबिनेट द्वारा संशोधित भारतनेट कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है, जिसके अंतर्गत भारतनेट चरण-I और चरण-II के मौजूदा नेटवर्क के उन्नयन और शेष 42,000 जीपी में नेटवर्क के निर्माण कार्य प्रस्तावित है। बीएसएनएल को परियोजना प्रबंधन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

(ग) से (ङ) गांवों, सरकारी संस्थानों, स्कूलों, डाकघरों और निजी क्षेत्रों सहित ग्राम पंचायतों, ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैः-

1. भारतनेट अवसंरचना को इंटरनेट कनेक्टिविटी के प्रावधान के लिए टीएसपी/आईएसपी को पट्टे पर दिया गया है।
2. ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित संस्थानों के लिए हाई-स्पीड डेटा कनेक्शन प्रदान करने के लिए बीबीएनएल/बीएसएनएल द्वारा उपयोगकर्ता मंत्रालयों/विभागों के साथ विचार विमर्श किया गया है।
3. इसके अतिरिक्त मांग पंजीकरण पोर्टल 'https://ruralfiber.bsnl.co.in' तैयार करके मंत्रालयों/विभागों के साथ साझा किया गया है।
4. बीएसएनएल ने ग्राम पंचायतों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में एफटीटीएच कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए फ्रेंचाइजी और रेवेन्यू शेयर पार्टनर के साथ फ्रेंचाइजी प्रबंधन प्रणाली (एफएमएस) तैयार की है।
5. ग्राम पंचायतों में नेटवर्क की उपलब्धता में सुधार करना

I. खराब /क्षतिग्रस्त ऑप्टिकल फाइबर केबल की मरम्मत के लिए नियोजित रखरखाव एजेंसियां और फाइबर रखरखाव एजेंसियां नियुक्त की गई हैं।

II. भारतनेट चरण- I और चरण- II के मौजूदा नेटवर्क के उन्नयन, शेष 42,000 जीपी में नेटवर्क के निर्माण, 10 वर्षों के लिए संचालन और रखरखाव के लिए संशोधित भारतनेट कार्यक्रम को कैबिनेट द्वारा दिनांक 04.08.2023 को मंजूरी दे दी गई है।

इसके अलावा, पिछले पांच वर्षों में महाराष्ट्र सहित ई-ग्रामस्वराज पर तैयार और उपलब्ध कराई गई ग्राम पंचायत विकास योजनाएं (जीपीडीपी) जिलेवार नीचे दी गई हैः-

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/ जिला पंचायत	**कुल ग्राम पंचायतें ***	**2024-25**	**2023-24**	**2022-23**	**2021-22**	**2020-21**
महाराष्ट्र	27951	27744	27661	27806	27878	27876
लातूर	786	784	784	784	785	785
उस्मानाबाद	622	618	621	622	622	622
सोलापुर	1024	1011	1014	1018	1027	1028
वाशिम	491	491	490	491	491	491
यवतमाल	1201	1200	1200	1199	1201	1201

** मार्च 2025 तक कुल जीपी*

इसके अतिरिक्त, मार्च 2019 से मार्च 2024 के साथ-साथ अक्टूबर 2024 तक भारतनेट के माध्यम से प्रदान किए गए ब्रॉडबैंड कनेक्शन की कुल संख्या **अनुलग्नक -III** में प्रदान की गई है।

(च) मंत्रालय वित्तीय वर्ष 2022-23 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की संशोधित केंद्र प्रायोजित योजना को लागू कर रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर), पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों को प्रशिक्षण देकर पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को सक्षम बनाना है, ताकि वे नेतृत्व भूमिकाओं के जरिए अपनी शासन क्षमता विकसित कर सकें और पंचायतों को प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बना सकें। योजना के तहत जिलों/ग्राम पंचायतों को नहीं बल्कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि जारी की गई है।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय स्वामित्व योजना लागू कर रहा है, जो एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका उद्देश्य ड्रोन-आधारित भूमि पार्सल मैपिंग के माध्यम से संपत्ति कार्ड/टाइटल डीड जारी करके ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में 'संपत्ति अधिकारों का रिकॉर्ड' प्रदान करना है। पंचायती राज मंत्रालय, राज्य राजस्व विभागों, राज्य पंचायती राज विभागों और भारतीय सर्वेक्षण द्वारा सहयोगात्मक रूप से कार्यान्वित की गई योजना से ग्रामीण आवासीय संपत्तियों के मुद्रीकरण की सुविधा मिलती है, संपत्ति विवाद कम होते हैं और डिजिटल मैपिंग के माध्यम से ग्राम-स्तरीय नियोजन में वृद्धि होती है, जिससे ग्रामीण आत्मनिर्भरता में योगदान मिलता है। 12 मार्च, 2025 तक, देश भर में 3.20 लाख गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है, जिसमें 1.59 लाख गांवों के लिए लगभग 2.42 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं।

महाराष्ट्र में करीब 37,609 गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है, जिससे 16,618 गांवों के लिए 2.60 लाख संपत्ति कार्ड तैयार हो चुके हैं। उस्मानाबाद और वाशिम-यवतमाल संसदीय क्षेत्र में हुई प्रगति इस प्रकार है:-

जिला	**ड्रोन उड़ान (गांव)**	**तैयार प्रोपर्टी कार्डों की संख्या**
लातूर	869	83450
उस्मानाबाद (धाराशिव)	725	31152
सोलापुर	1092	41327
वाशिम	677	42087
यवतमाल	1795	130555

*****

अनुलग्नक-I

'इंटरनेट और ई-पंचायत' के संबंध में दिनांक 18.03.2025 को दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2858 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान पंचायत स्तर पर ई-ग्रामस्वराज को अपनाना

क्र.सं.	राज्य का नाम	ग्राम पंचायत एवं समकक्ष की कुल संख्या	ऑनबोर्ड ग्राम पंचायत	ऑनलाइन भुगतान वाली ग्राम पंचायतें और समकक्ष	ब्लॉक पंचायत एवं समकक्ष की कुल संख्या	ऑनबोर्ड ब्लॉक पंचायत	ऑनलाइन भुगतान वाली ब्लॉक पंचायतें और समकक्ष	जिला पंचायत एवं समकक्ष की कुल संख्या	ऑनबोर्ड जिला पंचायत	ऑनलाइन भुगतान वाली जिला पंचायतें और समकक्ष
1	आंध्र प्रदेश	13328	13296	12970	660	660	642	13	13	13
2	अरुणाचल प्रदेश	2108	2106	222	0	0	0	27	25	8
3	असम	2662	2197	2176	191	191	189	30	29	27
4	बिहार	8054	8054	8045	534	534	530	38	38	38
5	छत्तीसगढ़	11596	11594	11516	146	146	146	27	27	27
6	गोवा	191	190	93	0	0	0	2	2	2
7	गुजरात	14656	14599	13890	248	248	248	33	33	33
8	हरियाणा	6226	6222	5914	143	143	134	22	22	22
9	हिमाचल प्रदेश	3615	3614	3540	81	81	81	12	12	12
10	झारखंड	4345	4345	4329	264	264	262	24	24	24
11	कर्नाटक	5954	5954	5937	238	232	126	31	31	28
12	केरल	941	941	941	152	152	152	14	14	14

13	मध्य प्रदेश	23011	23009	22980	313	313	310	52	52	52
14	महाराष्ट्र	27917	27894	26737	351	351	307	34	34	34
15	मणिपुर	3180	161	123	0	0	0	12	6	4
16	मेघालय	6817	0	0	2241	0	0	3	3	0
17	मिजोरम	842	842	832	0	0	0	0	0	0
18	नागालैंड	1289	186	0	0	0	0	0	0	0
19	ओडिशा	6794	6794	6793	314	314	314	30	30	30
20	पंजाब	13237	13222	9775	152	151	114	22	22	19
21	राजस्थान	11211	11207	10837	361	353	351	33	33	33
22	सिक्किम	199	199	195	0	0	0	6	6	6
23	तमिलनाडु	12525	12525	12519	388	388	388	36	36	36
24	तेलंगाना	12991	12768	12636	572	540	508	32	32	32
25	त्रिपुरा	1194	1185	1174	75	75	75	9	9	9
26	उत्तराखंड	7795	7794	7743	95	95	95	13	13	13
27	उत्तर प्रदेश	57691	57691	57609	826	826	818	75	75	75
28	पश्चिम बंगाल	3339	3339	3338	345	345	345	22	21	21
कुल		**263708**	**251928**	**242864**	**8690**	**6402**	**6135**	**652**	**642**	**612**

———

अनुलग्नक-II

'इंटरनेट और ई-पंचायत' के संबंध में दिनांक 18.03.2025 को दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2858 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

ब्रॉडबैंड कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए तैयार सेवा बिंदुओं का राज्यवार विवरण।

क्र.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ग्राम पंचायतों की कुल संख्या	तैयार सेवा बिंदुओं की संख्या *
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	70	81
2	आंध्र प्रदेश	13327	12972
3	अरुणाचल प्रदेश	2108	1145
4	असम	2665	1634
5	बिहार	8054	8860
6	छत्तीसगढ़	11623	9759
7	गोवा	191	0
8	गुजरात	14674	14563
9	हरियाणा	6225	6204
10	हिमाचल प्रदेश	3615	416
11	जम्मू और कश्मीर	4291	1115
12	झारखंड	4345	4649
13	कर्नाटक	5948	6251
14	केरल	941	1130
15	लद्दाख	193	193
16	लक्षद्वीप	10	9
17	मध्य प्रदेश	23011	18106
18	महाराष्ट्र	27952	24778
19	मणिपुर	3812	1485
20	मेघालय	6838	697
21	मिजोरम	843	539
22	नागालैंड	1315	236
23	ओडिशा	6794	7099
24	पुदुचेरी	108	101
25	पंजाब	13236	12807
26	राजस्थान	11193	8997
27	सिक्किम	199	54
28	तमिलनाडु	12525	10298
29	तेलंगाना	12860	10926
30	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	42	41

क्र.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ग्राम पंचायतों की कुल संख्या	तैयार सेवा बिंदुओं की संख्या *
31	त्रिपुरा	1194	772
32	उत्तर प्रदेश	57691	47451
33	उत्तराखंड	7788	2021
34	पश्चिम बंगाल	3339	2958
	कुल	269020	218347

*** डेटा भारतनेट यूएनएमएस डैशबोर्ड से प्राप्त किया जाता है, और कुछ ग्राम पंचायतों में कई सेवा-तैयार बिंदु हो सकते हैं।**

———

अनुलग्नक-III

इंटरनेट और ई-पंचायत' के संबंध में दिनांक 18.03.2025 को दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2858 के भाग (ग) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

भारतनेट के माध्यम से प्रदान किये गये संचयी ब्रॉडबैंड कनेक्शन की संख्या।

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मार्च,19	मार्च,20	मार्च,21	मार्च,22	मार्च 23	मार्च -24	अक्तूबर-24
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0	0	2	0	1185	5524	7347
2	आंध्र प्रदेश	19	450	7366	3585	3444	32173	46179
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	24	88	88	13	13
4	असम	740	986	5839	1136	2229	5024	5649
5	बिहार	870	118	33626	37012	15705	33768	40789
6	चंडीगढ़	0	0	55	0	64	0	0
7	छत्तीसगढ़	956	1201	17469	9513	4474	8277	11549
8	डी एंड एनएच	0	10	44	35	7	46	142
9	डी एंड डी	0	11	34	21	1	0	0
10	गुजरात	679	4592	33875	22897	20877	119604	121265
11	हरियाणा	183	803	33279	17597	37349	103665	137543
12	हिमाचल प्रदेश	3	94	1072	438	1095	2828	3451
13	जम्मू एवं कश्मीर (यूटी)	0	109	766	508	4022	8575	9575
14	झारखंड	711	921	15705	3010	11737	24338	27565
15	कर्नाटक	5122	8347	36666	10859	15196	44990	51098
16	केरल	1632	2179	2624	1941	40194	141927	190237
17	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0
18	लद्दाख(यूटी)					0	0	0
19	मध्य प्रदेश	2497	605	55044	7579	45218	48306	55381
20	महाराष्ट्र	3034	5304	66075	23386	11329	23228	26063
21	मणिपुर	0	0	100	335	1105	1110	1737
22	मेघालय	0	0	100	16	14	149	103
23	मिजोरम	0	0	21	0	32	9	41
24	नागालैंड	0	0	52	116	116	101	131
25	ओडिशा	191	1649	21057	9534	4911	9073	10907
26	पुदुचेरी	22	83	785	114	28	3072	3826
27	पंजाब	66	747	38994	33341	68560	177734	213118
28	राजस्थान	1622	1948	2376	1029	11579	42628	49252

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मार्च,19	मार्च,20	मार्च,21	मार्च,22	मार्च 23	मार्च -24	अक्तूबर-24
29	सिक्किम	0	0	8	0	15	41	44
30	तेलंगाना	144	526	2353	2648	4479	19854	20881
31	तमिलनाडु	0	0	0	0	1014	51	82
32	त्रिपुरा	0	651	2980	1426	709	1231	1370
33	उत्तर प्रदेश	3798	2360	106203	33444	13204	55711	67525
34	उत्तराखंड	856	561	8280	4647	4691	16072	19675
35	पश्चिम बंगाल	212	1041	7294	2886	15447	37091	51998
	कुल	**23357**	**35296**	**500168**	**229141**	**340118**	**966213**	**1174536**

———